दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश
PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in
संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 8 • अंक : 214 • मुंबई, गुरुवार 5 फरवरी, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

राष्ट्रपति का अभिभाषण परंपरा और प्रगति का संगम : जेपी नड्डा

संवाददाता

नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर बुधवार को चर्चा जारी रखते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का ज़िक्र कर उन्होंने कहा कि सरकार इसपर भी चर्चा के लिए तैयार है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अस्वस्थ होने के बावजूद मुंबई से दिल्ली आए, ताकि लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दे सकें लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने के कारण उनका भाषण नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौता संतुलित है और देशहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का नजरिया संकीर्ण है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की परंपराओं के साथ-साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की अद्भुत विकास यात्रा का शक्तिशाली प्रतिबिंब हमें देखने को मिला है। हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ ही वर्ष-2047 के विकसित भारत का समावेश राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है। उन्होंने कहा कि देश ने लंबा सफर तय किया है और प्रगति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम पहले किस स्थिति में थे। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत कभी "फ्रैजाइल फाइव" देशों में गिना जाता था, लेकिन आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश नीतिगत जड़ता (पॉलिसी पैरालिसिस) से निकलकर अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां देश घोटालों के लिए जाना जाता था, वहीं अब पारदर्शिता की क्रांति देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत पहले आयात पर निर्भर था लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि जीएसटी के बारे में भारी विरोध होने के बावजूद ये लागू हुआ, जिससे देश में सकारात्मक परिवर्तन आये है। वर्ष-2025 में आये जीएसटी 2.0 से भारत के आर्थिक विकास में तेजी आई है। पिछला सप्ताह भारत की आर्थिक क्रांति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रहा। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। वहीं भारतीय -ईयू व्यापार समझौते के बाद भारत और अमरिका व्यापार समझौता देश के आर्थिक विकास में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाने की बात की लेकिन भ्रष्टाचार किया। गरीबों के नाम पर वोटबैंक लिया लेकिन गरीबों को बैंक तक नहीं जाने दिया। गरीबों को शौचालय, पक्का आवास, पीएम-जनधन, उज्ज्वला योजना जैसी नीतियों से उन्हें कई अधिकार मोदी सरकार ने दिये हैं। मोदी सरकार में 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये की इलाज की गारंटी दी गई है, ये योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है। कांग्रेस की सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा जब राष्ट्रपति जी अपना वक्तव्य दे रहीं थीं तो विपक्ष ने उनके अभिभाषण में व्यवधान करते हुए नारे लगाये थे।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की दलीलें भले अच्छी लगें लेकिन ज़मीनी हकीकत इतनी खराब है कि उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई अहम मुद्दों पर चुप्पी रही। उन्होंने सदन के सामने सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले, अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसानों और मजदूरों के संघर्ष तथा विदेश नीति की कमियों जैसे विषय उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को सिर्फ भाजपा का वोट बैंक बनाकर देखा जा रहा है। खरगे ने सरकार से सवाल किया कि महिलाओं को आरक्षण अब तक पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कथनी और करनी के बीच के अंतर को दर्शाता है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गोलीबार रोड का सीसी निर्माण

बीएमसी रोड अभियंता व ठेकेदार की लापरवाही से धंसी सीसी रोड

संवाददाता

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के पश्चिम उपनगर सड़क विभाग के एच/पूर्व वार्ड क्षेत्र के अभियंताओं और ठेकेदार की कथित मिलीभगत का नतीजा एक बार फिर सामने आया है। खार (पूर्व) स्थित गोलीबार रोड पर किया गया सीसी रोड निर्माण घटिया गुणवत्ता का साबित हो रहा है, जो आम नागरिकों और यातायात के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 94 में खार पूर्व स्थित गोलीबार रोड पर लगभग एक वर्ष पूर्व सीसी सड़क का निर्माण किया गया था। निर्माण के समय से ही सड़क की हालत खराब होने लगी थी, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए थे। अब स्थिति यह है कि यह सड़क लगातार धंस रही है और दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। बुधवार को गोकुल

सुपर मार्केट के सामने एक डंपर के गुजरने के दौरान सीसी रोड का एक हिस्सा अचानक जमीन में धंस गया।

इस घटना से यह साफ हो गया है कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का गंभीर उल्लंघन किया गया है।

गौरतलब है कि दैनिक स्वर्णिम प्रदेश ने इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और नियमों के दुरुपयोग को लेकर पहले ही खबर प्रकाशित की थी। इसके बावजूद न तो संबंधित उप अभियंता, न ही कार्यकारी अभियंता और न ही मुख्य अभियंता स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई की गई। नतीजतन, आज इस लापरवाही और भ्रष्टाचार का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस घटिया निर्माण की तकनीकी जांच कब होगी, और दोषी अभियंताओं व ठेकेदार पर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी? यदि समय रहते जांच और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

गृहमंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल

संवाददाता

जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। वे शनिवार रात रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन रविवार को नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह

बस्तर के लिए निकलेंगे जहां वे बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई 31 मार्च 2026 की नक्सलवाद समाप्ति की तय की गई समय सीमा नजदीक आ चुकी है।

लखनऊ में होगी बजरंग दल की अखिल भारतीय बैठक

संवाददाता

लखनऊ। बजरंग दल की दो दिवसीय अखिल भारतीय बैठक आगामी 07 व 08 फरवरी को लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट में होगी। इस बैठक में देश के सभी क्षेत्र व 47 प्रान्तों के संयोजक, सह संयोजक सहित 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के उद्घाटन सत्र में विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, रंगमहल मंदिर अयोध्या के महंत राम शरण दास महराज, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक

किशन प्रजापति और सह संयोजक विवेक कुलकर्णी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी बजरंग दल के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक पूर्णेन्दु ने बुधवार को दी। क्षेत्र संयोजक पूर्णेन्दु ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि प्रयागराज व अयोध्या में बैठक हो चुकी हैं लेकिन लखनऊ में बजरंग दल की अखिल भारतीय बैठक पहली बार हो रही है।

स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सनातन संस्कृति के प्रमुख संवाहक: मुख्यमंत्री फडणवीस

समाधि मंदिर भावी पीढ़ियों के लिए बनेगा प्रेरणाकेंद्र

संवाददाता

हरिद्वार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने सनातन संस्कृति के प्रमुख संवाहक के रूप में जीवनभर कार्य किया, जिसके कारण आज नई पीढ़ी के समक्ष भारतीय

संस्कृति की महान परंपरा सशक्त रूप में उपस्थित है। उन्होंने कहा कि स्वामीजी का समाधि मंदिर भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा। बुधवार को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरीजी महाराज के समाधि मंदिर में श्रीविग्रह मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प.पू. जुनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरीजी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के स्वामी गोविंददेव गिरीजी, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सहित अनेक संत-महंत एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारतीय संस्कृति की संत परंपरा समाज को एकसूत्र में बांधने का कार्य करती है। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से इस परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई।

शेष पेज 2 पर...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन

भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा दौरे के तीसरे दिन बुधवार को पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व उन्होंने पारंपरिक पितृ कर्म भी संपन्न किए। पुरी पहुंचने पर राष्ट्रपति ने सबसे पहले श्वेतगंगा में पिंडदान किया, जो पितृ अनुष्ठानों से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। इसके बाद वह श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचीं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के दौरान ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपटि और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। दर्शन के उपरांत श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति को खंडुआ रेशमी वस्त्र और ओडिशा की पारंपरिक कला पट्टचित्र भेंट किया गया। इस पट्टचित्र में भगवान जगन्नाथ को केंद्र में रखते हुए दशावतार का सजीव चित्रण किया गया है। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मंदिर में सुबह 10 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन स्थगित रहे, ताकि गोपाल वल्लभ भोग सहित सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

संसद परिसर में राहुल गांधी-रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक

संवाददाता

नई दिल्ली। संसद परिसर में बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व सहयोगी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने बिट्टू को 'गद्दार' कहा तो जवाब में बिट्टू ने उन्हें 'देश का दुश्मन' करार दिया।

यह घटना संसद के मकर द्वार के बाहर हुई जहां कांग्रेस सांसदों के निलंबन के विरोध में पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी निलंबित कांग्रेस सांसदों, जिनमें अधिकांश पंजाब से थे, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए मकर द्वार के पास खड़े थे। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुज़रे।

प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के मुताबिक, राहुल गांधी ने बिट्टू को देखते हुए कहा, "देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। इसका चेहरा देखो।" इसके बाद उन्होंने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, "नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे। हालांकि, रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटवार करते हुए कहा, "देश के दुश्मन"। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बातचीत होती दिखी। घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब को आग में झोंक दिया था और गोल्डन टेंपल पर गोलियां चली थीं। उन्होंने कहा कि हजारों सिखों और पंजाबियों को निशाना बनाया गया। बिट्टू ने यह भी कहा कि जब तक वे कांग्रेस में थे, तब तक उन्हें शहीद का पोता कहा जाता था लेकिन भाजपा में आने के बाद उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी की सिरसा ने की निंदा, कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मंत्री सिरसा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद परिसर में सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्हें गद्दार कहा, इसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि सिख सरदार है, वह कभी गद्दार नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री मोदी ने हास्य के महत्व पर साझा किया सुभाषित

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को एक्स पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए जीवन में हास्य के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया , "औषधेष्वपि सर्वेषु हास्यं श्रेष्ठं वदन्ति ह। स्वाधीनं सुलभं चैवारोग्यानन्दविवर्धनम्॥" इसका अर्थ है कि सभी औषधियों में निश्चय ही हंसना श्रेष्ठ औषधि है क्योंकि यह आसानी से बिना मूल्य के उपलब्ध हो जाती हैं तथा स्वास्थ्य और आनंद की वृद्धि करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुभाषित के माध्यम से बताया कि सभी औषधियों में हास्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह सहज रूप से उपलब्ध है और स्वास्थ्य व आनंद दोनों को बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस संदेश को सकारात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन से जोड़कर देखा है।

संपादकीय

संपादकीयः चीन, चुप्पी और सरकार !

स्मरण होगा, चंद दिनों पूर्व चीनी राजनीतिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बीजेपी मुख्यालय में गोपनीय बातें और मुलाक़ात हुई। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने कहा था, चीन हमारा पुराना शत्रु है। पाकिस्तान को तो हम जब चाहें धूल चटा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भारत पर रूस से तेल लेने के नाते 25 प्रतिशत अधिक टैरिफ की घोषणा की तो प्रधानमंत्री तुरंत चीन में होने वाली बैठक में गए, जहां वे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, तब जिनपिंग ने आगे बढ़ने का इशारा किया। मजबूर मोदी जी को अपमानित होकर आगे जाना पड़ा था। पाकिस्तान के साथ शारजाह में क्रिकेट खेल सकते हैं, परंतु पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिला सकते। बड़े गर्व से कहा गया कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। कुछ ऐसा ही भाव जिनपिंग का रहा होगा। बहुत समय से कहा जा रहा है चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर कई नाम बदले। लद्दाख के चरवाहों ने बताया था कि जहां उनकी भेड़-बकरियां चराई जाती थीं, अब वहां जाने से चीनी सेना मना करती है। अगर यह सच है तो बेहद चिंता का विषय है। राहुल गांधी पर चीनी राजदूत से मिलने पर बीजेपी तंज कसती रही थी, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में चीन की राजनीतिक पार्टी के साथ मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? चीन के साथ हमारा पुराना विवाद रहा है, जब चीन ने हिंदी-चीनी भाई-भाई कहते हुए हमारी पीठ में छुरा घोंपा और हजारों वर्ग किलोमीटर हमारी भूमि पर कब्जा जमा लिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी ने कहा था कि लाल आंखें दिखानी चाहिए थीं। तब भारत मजबूर था, कमजोर था, इसलिए लाल आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन आज तो भारत सुरक्षित हाथों में मजबूत बताया जाता है, फिर क्यों लाल आंखें नहीं दिखाता? चीन के साथ सीमा विवाद हमेशा रहा है। साम्राज्यवादी चीन शक्तिशाली बन चुका है। फिर जब बीजेपी चीनी पदाधिकारियों के साथ मुख्यालय में गुफ्तगू कर रहा था, ठीक उसी समय चीन भारतीय भूमि को अपना होने का दावा क्यों और किस अधिकार से कर रहा था? चीन की नीति है अंगुल-अंगुल पड़ोसी राष्ट्रों की भूमि पर कब्जा जमाना। दोकलाम और गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प हो चुकी है। गलवान घाटी में हमारे बीस जवान मारे गए थे। पूर्व जनरल आर्मी चीफ नरवरे ने अपनी किताब में लिखा है, जो वर्षों से प्रकाशित होने के लिए सरकार की अनुमति के लिए दबा कर रखी गई है। निश्चित ही सरकारी लोग इस पांडुलिपि को पढ़ चुके होंगे, जिसमें नरवरे ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज्ञा मांगी थी ताकि चीनी सेना द्वारा हो रही घुसपैठ को रोका जा सके। लेकिन आज्ञा नहीं दी गई। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय सरकार और गोदी मीडिया ने बड़ा शोर किया था कि मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि स्थान और समय सेना तय करे, लेकिन यह प्रचार सफेद झूठ निकला, क्योंकि खुद आर्मी चीफ ने सिंगापुर में कहा था, सरकार झूठ बोल रही है। हमें खुली छूट नहीं दी गई थी, बल्कि पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की सख्त मनाही थी। यही नहीं, सेना जब शौर्य दिखा रही थी तब सरकार पाकिस्तानी आईएसआई चीफ को खुफिया जानकारी दी जा रही थी कि हमारी सेना आतंकवादियों और उनके अड्डे तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। पाकिस्तान को सचेत करना सरकार का ब्लंडर था, क्योंकि हमारे कई विमान मार गिराने का दावा पाकिस्तान करने लगा था। आर्मी चीफ रहे नरवरे ने जो किताब लिखी है, उसकी प्रमुख घटनाएं अखबार और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए नरवरे की अप्रकाशित पुस्तक के अंश बोलने लगे थे। संसद में पीएम मोदी विदेशी लेखक को कोट करते थे। बीजेपी के नेता भी कई बार किताबों में लिखी बातों को कोट करते रहे हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी को फायदा दिखता रहा। लेकिन जब भारतीय सेनाध्यक्ष की पुस्तक से कोट किया गया तो गृहमंत्री, रक्षामंत्री ही नहीं, खुद स्पीकर भी राहुल गांधी को संसद का कानून बताने लगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब राहुल गांधी का समर्थन किया तो स्पीकर ने उनकी माइक ही बंद कर दी। क्या निष्पक्ष हैं स्पीकर या बीजेपी के अधिकारी? कम से कम स्पीकर पद की मर्यादा का ख्याल रखते। जो कानून सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होता, वह विपक्ष पर क्यों थोपा जाता है? नरवरे ने जब सरकार से अनुमति मांगी थी तब उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई? किताब में लिखा चूंकि बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, इसलिए सारे कानून लागू किए जाना लोकतंत्र का अपमान नहीं तो क्या है? जब सेना ने सरकार से एयरलिफ्ट कराने के लिए हवाई जहाज मांगे थे, तब पांच महीने तक फाइल गृहमंत्रालय ने दबा कर रखी थी। मजबूरन रोड मार्ग से सेना को जाना पड़ा और देश के चालीस वीर सैनिकों को अपने प्राण कुर्बान करने पड़े थे। पहलगाम हमले के दो दिन पूर्व वहां से सुरक्षा हटा ली गई, जिससे 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था। आज तक इतना अधिक आरडीएक्स कहां से आया, इसका पता नहीं लगा सकी सरकार। चीन के मामले में सरकार चुप हो जाती है। भले ही सेनाध्यक्ष नरवरे की किताब सरकार ने प्रकाशित नहीं होने दी हो, लेकिन उसके कई अंश पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जिस पर कभी सेनाध्यक्ष ने असहमति नहीं जताई। नरवरे के अनुसार किताब का प्रकाशित होना प्रकाशक और सरकार के बीच का मामला है। आखिर क्यों रोका गया राहुल गांधी को सच कहने से? शायद सरकार को सच हजम नहीं हो पाता। हजारों वर्ष पूर्व वेद, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, रामायण, वैमानिक शास्त्रम, पतंजलि महाभाष्य जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें ताड़ पत्रों आदि पर लिखी गई थीं। रामचरितमानस तुलसीदास ने कई बार लिखी और प्रेमियों में वितरित की। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में हजारों पांडुलिपियां रखी गई हैं। शोध छात्र उन पर पीएचडी करते रहते हैं। उन्हें डिग्रियां भी दी जाती हैं। अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रामाणिक माना जाता है। उन्हीं का मैक्स मूलर अनुवाद करता है। तब नरवरे जो अनुशासित सेनाध्यक्ष रहे हैं, उनकी किताब छापने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई सरकार द्वारा, तो क्या उनकी पुस्तक को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता? सेना अनुशासित होती है, इसीलिए नरवरे की किताब डिजिटल रूप में बाजार में उपलब्ध नहीं है।

पेज 1 का शेष...

स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सनातन संस्कृति के प्रमुख संवाहकः मुख्यमंत्री फडणवीस

उन्होंने विश्वभर में फैले सनातन संस्कृति के प्रवाहों को एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वामीजी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा को समर्पित किया। आपदा और संकट के समय उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य कर सनातन संस्कृति की करुणामयी छवि को सशक्त किया। कई अवसरों पर उन्होंने पद और प्रतिष्ठा का त्याग कर अपने वैश्विक दायित्वों को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति आज भी अपनी मूल चेतना के साथ जीवित है। सरस्वती सभ्यता के उत्खनन से सनातन विचारों के प्राचीन अस्तित्व को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पुष्टि मिली है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जीवन पद्धति और सनातन संस्कृति समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति मिली है। इसके कारण युवा पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ रही है और भारतीय परंपराओं पर गर्व कर रही है। इस सांस्कृतिक पुनरोत्थान में संतों और महंतों का योगदान अमूल्य है।

एल.आई.सी

भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह

मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

विदेश यात्रा से वापसी पर कितना सोना ला सकते हैं? नए नियमों ने किया साफ

संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

विदेश यात्रा से लौटते समय यात्रियों के सामान को लेकर अक्सर असमंजस और विवाद की स्थिति बनती रही है। खासकर सोना, चांदी और आभूषणों को लेकर नियमों की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण कई बार यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुराने बैगेज नियमों को बदल दिया है। वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी 2026 से कस्टम्स बैगेज (डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) रेगुलेशंस, 2026 को लागू कर दिया है, जिससे 2016 के बैगेज नियमों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाना, नियमों को सरल बनाना और व्याख्या से जुड़े विवादों को खत्म करना है। नए बैगेज नियम 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा आभूषणों, विशेष रूप से सोने और चांदी के गहनों को लेकर हो रही है। अब तक यात्रियों के मन में यह सवाल बना रहता था कि विदेश से कितना सोना या चांदी लाया जा सकता है और उस पर कितना शुल्क देना होगा। नए नियमों में 'ज्वेलरी' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सोने और चांदी दोनों के आभूषण शामिल माने गए हैं। नियमों में अलग से यह नहीं बताया गया है कि ज्वेलरी सोने की है या चांदी की, बल्कि कुल वजन को आधार बनाया गया है।

इन नियमों के तहत यदि कोई भारतीय निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक, जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है, भारत आता है तो उसे सीमित मात्रा में आभूषण बिना किसी कस्टम ड्यूटी के लाने की अनुमति होगी। महिला यात्री के लिए यह सीमा 40 ग्राम तक तय की गई है, जबकि महिला के अलावा अन्य यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम रखी गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई महिला यात्री दुबई, सिंगापुर, यूरोप या किसी भी अन्य देश से भारत लौटती है और उसके पास 40 ग्राम तक के सोने या चांदी के आभूषण हैं, तो उसे किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। इसी तरह पुरुष यात्री 20 ग्राम तक के आभूषण बिना शुल्क के ला सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। नए नियमों के अनुसार, सभी यात्रियों को भारतीय सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इस फॉर्म में यात्रियों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे कौन-कौन से सामान अपने साथ ला रहे हैं, जिनमें आभूषण भी शामिल हैं। यदि यात्री द्वारा लाए गए आभूषण दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सीमा से अधिक हैं या निर्धारित विशेष छूट से ज्यादा हैं, तो उन्हें इसकी घोषणा करनी होगी। घोषणा में कुल व्यक्तिगत आभूषणों का वजन, चाहे वे नए हों या पुराने, और कुल लाए गए आभूषणों का वजन स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।

यदि किसी यात्री द्वारा लाए गए आभूषणों का वजन निर्धारित ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक पाया जाता है, तो अतिरिक्त वजन पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। नए नियमों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुल्क केवल उसी मूल्य या वजन पर लगेगा, जो ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक होगा, न कि पूरे सामान पर। इससे यात्रियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। बैगेज नियम 2026 केवल आभूषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें अन्य वस्तुओं के लिए भी ड्यूटी-फ्री सीमाएं तय की गई हैं। भारतीय निवासी, भारतीय मूल के पर्यटक या वैध वीजा वाले विदेशी नागरिक, जो भूमि मार्ग के अलावा किसी अन्य माध्यम से भारत आते हैं, वे 75,000 रुपये मूल्य तक का सामान बिना शुल्क के ला सकते हैं। वहीं, विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये रखी गई है। हालांकि, जो यात्री भूमि मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं, उनके लिए ड्यूटी-फ्री सामान की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, सभी यात्रियों को दो लीटर तक शराब या वाइन बिना शुल्क के लाने की अनुमति दी गई है। तंबाकू उत्पादों के मामले में भी सीमा तय की गई है, जिसके तहत यात्री 100 सिगरेट, 25 सिगार या 125 ग्राम तंबाकू ला सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों को एक नया लैपटॉप या नोटपैड बिना किसी कस्टम ड्यूटी के लाने की छूट दी गई है। ये प्रावधान यात्रियों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि बार-बार होने वाली पूछताछ और जब्ती की स्थिति से बचा जा सके। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैगेज नियमों में यह बदलाव कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है नियमों का सरलीकरण और युक्तिकरण, ताकि यात्रियों और कस्टम अधिकारियों दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो। इसके अलावा, एयरपोर्ट पर यात्रियों से जुड़ी समस्याओं को कम करना, नियमों की व्याख्या को लेकर होने वाले विवादों का समाधान करना और अस्थायी रूप से लाए या ले जाए गए सामान की स्पष्ट व्यवस्था करना भी इन नियमों का उद्देश्य है। नए नियमों में भारतीय निवासियों और विदेशी पेशेवरों के लिए निवास स्थानांतरण से जुड़ी सुविधाओं को भी उनके भारत में रहने की अवधि के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। नए बैगेज नियमों में कुछ वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित भी किया गया है। इनमें ऐसे नक्शे और साहित्य शामिल हैं, जिनमें भारत की बाहरी सीमाओं को गलत तरीके से दर्शाया गया हो। इसके अलावा, मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सामान, वन्यजीव उत्पाद, भारतीय नकली मुद्रा और सिक्के, तथा कुछ निर्दिष्ट जीवित पक्षी और जानवर भारत लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन वस्तुओं के साथ पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर, बैगेज नियम 2026 को यात्रियों के लिए एक राहत भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है। खासकर सोने और चांदी के आभूषणों को लेकर जो असमंजस बना रहता था, उसे इन नियमों ने काफी हद तक दूर कर दिया है। अब यात्रियों को स्पष्ट रूप से पता है कि वे कितनी मात्रा में आभूषण बिना शुल्क के ला सकते हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि एयरपोर्ट पर कस्टम प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुचारू हो सकेगी। 2 फरवरी 2026 से लागू हुए ये नियम आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आज का राशिफल

मेषः विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। थकान रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। पराक्रम बढ़ेगा। जीवनसाथी से आर्थिक मतभेद हो सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप स्थिति बनेगी। संतान के व्यवहार पर नजर रखें।

वृषभः बुरी खबर मिल सकती है। आर्थिक तंगी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से लाभ होगा। आपसी विचार-विमर्श लाभप्रद रहेगा।

मिथुनः मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा सफल रहेगी। धनलाभ होगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। वाहन सुख मिलेगा। संपत्ति के लेन-देन में सावधानी बरतें। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। संतान पर ध्यान दें। जल्दबाजी व भागदौड़ से कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ।

कर्कः उत्साहवर्द्धक सूचना मिलेगी। स्वाभिमान बढ़ेगा। पुराने मित्र-संबंधी मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न बाधाओं से मन अशांत रहेगा। विवादों से दूर रहना चाहिए। पिछले कार्यों को टालें। पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा। व्यापार में हानि हो सकती है।

सिंहः राजकीय सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ होगा। जोखिम बिलकुल न लें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। व्यापार व नौकरी में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। गृह उपयोगी वस्तुएँ क्रय करेंगे। नए संबंधों के प्रति सतर्क रहें।

कन्याः फालतू खर्च होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। कुसंगति से बचें। दूसरों पर भरोसा न करें। धैर्य रखें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। रुका पैसा मिलेगा। शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। अतः सावधान रहें। व्यापार में सफलता मिलेगी।

तुलाः रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। विवाद न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। पूँजी निवेश बढ़ेगा। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक योग शुभ हैं। यात्रा से व्यापारिक लाभ हो सकता है। सुसंगति से लाभ होगा।

वृश्चिकः योजना फलीभूत होगी। नए अनुबंध होंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। जल्दबाजी व भागदौड़ से काम करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ। अच्छे मित्र से भेंट होगी। पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज-परिवार में आदर मिलेगा।

धनुः धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। कार्यसिद्धि होगी। आय-व्यय में संतुलन रहेगा। क्रोध पर संयम आवश्यक है। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी। नई योजना से लाभ होगा।

मकरः वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार के विस्तार हेतु किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। परिवार की चिंता रहेगी।

कुंभः प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। राजकीय बाधा दूर होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रुभय रहेगा। लाभ होगा। पिछले कार्यों को टालना चाहिए क्योंकि उसमें असफलता का योग है। अनावश्यक विवाद होगा। व्यावसायिक योजनाएँ क्रियान्वित नहीं हो पाएँगी।

मीनः संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। खर्चों में वृद्धि से चिंता होगी। संतान के रोजगार की समस्या का समाधान संभव है। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। कश्मकश दूर होगी। स्वजनों से भेंट होगी।

महापौर चुनाव में देरीः मुंबईकरों के जनादेश की परीक्षा

अनिल गलगली
सूचना अधिकार कार्यकर्ता

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी 2026 को संपन्न हुए और 16 जनवरी को परिणाम घोषित कर दिए गए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका था। लेकिन लोकतंत्र का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण चरण था सत्ता का त्वरित हस्तांतरण जो यहीं आकर धीमा पड़ गया। महापौर का चुनाव 11 फरवरी 2026 को तय किया गया, यानी चुनाव परिणामों के बाद पूरे 26 दिनों की देरी। यह देरी केवल एक प्रशासनिक संयोग है या सत्ता की सुविधा के लिए की गई रणनीति, यह सवाल आज पूरे शहर में गूंज रहा है। मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि महापौर का चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए।

हालांकि, यह अनिवार्य है कि पहली आम सभा अनावश्यक विलंब के बिना आयोजित की जाए। भले ही कानून में दिनों की स्पष्ट संख्या न हो, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा साफ कहती है कि जनता के फैसले को टालना नहीं चाहिए। कानून की खामियों का लाभ उठाना प्रशासन का कर्तव्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं में चुनाव परिणामों के 10 से 15 दिनों के भीतर महापौर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहां भी कानून वही है, नियम वही हैं। फिर मुंबई के लिए अलग समय-सारणी क्यों? उत्तर स्पष्ट है कि मुंबई में लोकतंत्र से अधिक राजनीतिक गणित जटिल हैं। परिणामस्वरूप, चुने हुए नगरसेवक अधिकारविहीन

रहते हैं और प्रशासक अधिक समय तक सत्ता में बने रहते हैं। जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलता और प्रशासनिक तंत्र को अतिरिक्त स्वायत्तता मिलती है, तो सवाल उठता है कि इसका लाभ किसे होता है? निश्चित रूप से जनता को नहीं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपने में देरी करना, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को दरकिनार करने जैसा है। "महानगर बड़ा है", "सुरक्षा का मुद्दा है", "तैयारियों में समय लगता है" ये तर्क बार-बार दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यही कारण अन्य बड़े शहरों में बाधा क्यों नहीं बनते? क्या प्रशासन स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या फिर सत्ताधारियों की सुविधा के अनुसार समय तय किया जा रहा है? इस पर संदेह होना स्वाभाविक है। महिला महापौर बनने की संभावना स्वागतयोग्य है। लेकिन यदि निर्णय प्रक्रिया ही समय पर न हो, तो ऐसी घोषणाओं का लोकतांत्रिक मूल्य क्या रह जाता है? प्रतिनिधित्व केवल नाम का नहीं, बल्कि समय पर अधिकार देने से सिद्ध होता है। 11 फरवरी 2026 की तारीख भले ही कानूनी दायरे में हो, लेकिन लोकतंत्र केवल कानून से नहीं चलता; वह नैतिकता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर आधारित होता है। जो कानूनी है, वही हमेशा न्यायसंगत हो ऐसा आवश्यक नहीं।

यह मुद्दा केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं है। भविष्य में क्या इसी तरह 40–50 दिनों तक देरी नहीं की जाएगी, इसकी गारंटी कौन देगा? इसलिए महापौर चुनाव के लिए कानून में स्पष्ट समय-सीमा (Time-limit) तय करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा लोकतंत्र केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यदि उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही धीमी होगी, तो संदेश गलत जाएगा। मुंबईकरों ने अपना जनादेश दे दिया है। अब प्रशासन और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जनादेश को समय पर, ईमानदारी से और पारदर्शी तरीके से लागू करें। लोकतंत्र सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि जनता के समय पर चलना चाहिए।

मुंबई में MHADA की बिना लॉटरी आवास योजना शुरू

संवाददाता

मुंबई। सपनों के शहर मुंबई में घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (MHADA) ने मुंबई बोर्ड के तहत खाली पड़े 120 आवासीय फ्लैट्स को बेचने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस बार आपको घर पाने के लिए महीनों तक लॉटरी के नतीजों का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि म्हाडा ने इन्हें 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

म्हाडा के अनुसार, इन फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 5 फरवरी 2026, सुबह 11 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो पिछली लॉटरी योजनाओं में चूक गए थे। ये वो फ्लैट्स हैं जो पहले की लॉटरी योजनाओं में शामिल थे, लेकिन किन्हीं कारणों से खाली रह गए थे।

पंजीकरण: 5 फरवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से।

आवेदन और फ्लैट चयनः 12 फरवरी 2026, सुबह 11:00 बजे से आवेदन भरने, बयाना राशि (EMD) जमा करने और पसंदीदा फ्लैट चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी।

पेमेंट की शर्त: एक बार फ्लैट आवंटित होने के बाद, आवेदक को 48 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

म्हाडा ने इन 120 फ्लैट्स को दो श्रेणियों में बांटा है:

म्हाडा निर्मित फ्लैट्स (84 फ्लैट्स): ये फ्लैट्स कांदिवली (शिंपोली, चारकोप सेक्टर-8), वडाला (एंटॉप हिल), पवई (तुंगा), मानखुर्द और मालाड (मालवणी गायकवाड़ नगर) जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं।

DCR कोटे के फ्लैट्स (36 फ्लैट्स): विकास नियंत्रण नियम 33(5) और 33(7) के तहत घाटकोपर पूर्व, विक्रोली, भायखला, ताड़देव, लोअर परेल, सायन और अंधेरी पश्चिम जैसे प्रीमियम इलाकों में घर उपलब्ध हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चूंकि यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' पर आधारित है, इसलिए पारदर्शिता और तेजी के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है।

मध्य रेलवे की M-UTS योजना से टिकट लाइनों में राहत

संवाददाता

मुंबई। मुंबई के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर यात्री टिकटों के लिए लगने वाली लंबी लाइन से राहत देने मध्य रेल द्वारा शुरू की एम-यूटीएस सहायक योजना को अच्छा प्रतिसाद मिलता दिख रहा है। डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के साथ यात्रियों की सुविधा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, मध्य रेल ने सीएसएमट मुंबई में एम-यूटीएस (मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली) सहायक योजना का शुरुआत की। बिना आरक्षण टिकट जारी करने हेतु एक स्मार्ट, प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था की गई है। इस पहल के तहत प्रशिक्षित एम-यूटीएस सहायकों को मोबाइल फोन एवं ब्लूटूथ-सक्षम प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से वे टिकट काउंटरों के निकट तथा यात्री विचरण क्षेत्र में घूम कर बिना आरक्षण टिकट जारी करते हैं। इससे यात्रियों को टिकट खिड़कियों की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. स्वप्निल नीला के अनुसार शुरुआत में 3 सहायकों की तैनाती से टिकट काउंटरों पर कतारों में उल्लेखनीय कमी आई है, टिकटिंग प्रक्रिया तेज़ हुई है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों को राहत हुई है। पिछले 3 माह में सीएसएमटी पर एम-यूटीएस सहायकों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। नवंबर 2025 में 37,267 टिकट जारी हुए और 54,169 यात्रियों को लाभ, दिसंबर 2025 में 49,167 टिकट जारी, 70,462 यात्रियों को लाभ और जनवरी 2026 में 50,306 टिकट जारी कर 72,569 यात्रियों को लाभ मिला। इस तरह तीन महीनों में सीएसएमटी पर एम-यूटीएस सहायक योजना से 1।97 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ मिला।

बताया गया कि एम-यूटीएस पहल के अतिरिक्त, मुंबई मंडल ने स्वचालित टिकटिंग को भी सुदृढ़ किया है। मुंबई मंडल के 88 स्टेशनों पर कुल 803 एटीवीएम उपलब्ध हैं। इसके अलावा 332 नए एटीवीएम की खरीद की गई है, जिनमें से 248 मशीनें मुंबई मंडल के स्टेशनों पर जल्द स्थापित की जाएंगी।

पुणे में पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार

संवाददाता

पुणे। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के सफल संचालन के लिए जिले की 13 तहसीलों में कुल 23,114 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इंदापुर तहसील में सबसे अधिक 2,632 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जबकि जुन्नर में 2,411 और खेड़ में 2,216 कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 2026 के कामकाज के लिए जिले के 13 तहसीलों में कुल 23 हजार 114 जनशक्ति की नियुक्ति की गई है, इसके तहत बारामती तहसील में 1 हजार 945, मावल 1 हजार 612, मुलशी 1 हजार 495, शिरूर 2 हजार 190, हवेली 1 हजार 800, दौड 2 हजार 60, इंदापुर 2 हजार 632, पुरंदर 1 हजार 538, भोर 1 हजार 190, वेल्हे 450, आंबेगांव 1 हजार 575, जुन्नर 2 हजार 411 और खेड़ तहसील में 2 हजार 216 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी सौंपी गई है।

पुणे कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि जिले में कुल 3 हजार 605 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें बारामती तहसील में 299, मावल 243, मुलशी 227, शिरूर 337, हवेली 263, दौंड 317, इंदापुर 400, पुरंदर 235, भोर 237, वेल्हे 105, आंबेगांव 239, जुन्नर 366 और खेड़ तहसीलों में 337 मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रशासन ने इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए एक विशेष पहल की है, जिसके तहत प्रत्येक तहसील में एक-एक के अनुसार कुल 13 आदर्श मतदान केंद्र और 13 महिला मतदान केंद्र (सखी बूथ) बनाए जाएंगे। चुनाव के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलेक्टस जितेंद्र डूडी ने नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव संबंधी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 020-26123371 या टोल-फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें-यह कक्ष चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष औस पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। पुणे ग्रामीण जिले में शाति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट ज्योति कदम ने 6 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत लागू यह आदेश जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, लाठी, विस्फोटक या किसी भी घातक वस्तु को साथ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, किसी व्यक्ति या नेता के पुतले का दहन, आपत्तिजनक नारेबाजी और उत्तेजक भाषणों पर भी रोक लगाई गई है। धारा 37(3) के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और पुलिस की अनुमति के बिना सभा या जुलूस निकालने की मनाही है। यह नियम सरकारी ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र कर्मियों पर लागू नहीं होगा, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 135 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल सिस्टम से टिकट रद्द करने की नई व्यवस्था लागू

संवाददाता

नागपुर। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सीटों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए टिकटिंग व्यवस्था में एक अहम बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन से 15 मिनट के भीतर अपनी आवंटित सीट पर पहुंचना अनिवार्य होगा। तय समय में सीट पर नहीं पहुंचने की स्थिति में संबंधित यात्री का टिकट स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे ने इसके लिए टीटीई (टिकट जांच कर्मचारी) को दिए जाने वाले एचएचटी (हैंड हेल्ड टर्मिनल) डिवाइस को अपडेट किया है। इस तकनीकी अपडेट के बाद अब टीटीई को रियल टाइम में यह जानकारी मिलेगी कि कौनसा यात्री बोर्डिंग स्टेशन से चढ़कर अपनी सीट पर पहुंचा है और कौन नहीं। यदि कोई आरक्षित यात्री निर्धारित समय सीमा में अपनी सीट पर नहीं पहुंचता तो उसका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार टिकट रद्द होते ही वह सीट आरएसी या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दी जाएगी। जैसे ही सीट खाली पाई जाती है टीटीई एचएचटी के माध्यम से तुरंत 'नोट प्रेजेंट' दर्ज करेगा जिसके बाद सिस्टम स्वतः अगली प्राथमिकता वाले यात्री को सीट अलॉट कर देगा।

इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी आरएसी या वेटिंग टिकट धारक यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य यात्रा के दौरान खाली सीटों की समस्या को खत्म करना है। अक्सर देखा गया है कि कई यात्री बोर्डिंग स्टेशन बदल लेते हैं या यात्रा ही नहीं करते लेकिन उनकी सीटें काफी दूरी तक खाली रहती हैं। इससे आरएसी और वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। नई प्रणाली से ऐसी स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। पहले की व्यवस्था में टीटीई को बोर्डिंग स्टेशन के बाद अगले 1 या 2 स्टेशनों तक इंतजार करना पड़ता था। इसके चलते सीटों का त्वरित उपयोग नहीं हो पाता था और पूरी प्रक्रिया मैनुअल होने के कारण पारदर्शिता पर भी सवाल उठते थे। अब डिजिटल सिस्टम के जरिए तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा जिससे यात्रा अधिक सुव्यवस्थित होगी।

रेलवे का मानना है कि यह बदलाव यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक, न्यायसंगत और पारदर्शी साबित होगा। आरक्षित टिकट लेकर यात्रा न करने की प्रवृत्ति पर भी इससे अंकुश लगेगा। साथ ही वेटिंग और आरएसी यात्रियों को यात्रा के दौरान सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर रेलवे की यह नई पहल आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीट प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम मानी जा रही है जिससे आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना से महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प

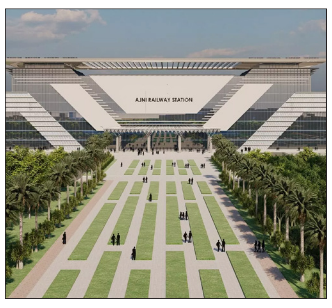

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत राज्य में पांच उपनगरीय स्टेशनों सहित 17 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें आमगांव, चंदा फोर्ट, चिंचपोकली,देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहद, वडाला रोड, बारामती और नंदुरा शामिल हैं। लोकसभा में बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान शिवसेना (शिंदे) सांसद श्रीकांत शिंदे, रविंद्र वायकर, श्रीरंग बारणे और नरेश म्हस्के के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने अमृत भारत योजना में पहचाने गए महाराष्ट्र के कुछ स्टेशनों की प्रगति का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास कार्य को स्वीकृति दे दी गई है। लंबी दूरी के नोड भवन, लंबी दूरी के कॉनकोर्स और पैदल पार पुल संख्या एक और दो के लिए नींव रखने का कार्य शुरू कर दिया है। दिवा स्टेशन भवन में सुधार, नया प्रवेश द्वार, कल्याण और मुंबई छोर पर पैदल पार पुल में सुधार समेत कई अन्य कार्य शुरु कर दिए गए है। इसके साथ ही मुंब्रा, टिटवाला, विक्रोली, चर्नी रोड, मालाड, कल्याण, दादर, ठाणे और पुणे स्टेशनों के पुनर्विकास का भी कार्य चल रहा है। प्रतीक्षा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र के सात स्टेशनों की पहचान कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड और शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय दीना पाटील के पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री ने बताया कि देश भर में होल्डिंग/प्रतीक्षा क्षेत्रों के निर्माण के लिए 76 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के सात रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में बांद्रा टर्मिनस शामिल हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, नागर, नाशिक रोड पुणे स्टेशन शामिल हैं।

पुणे–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर टैंकर हादसा

139 बस सेवाएं रद्द, 163 वाहन जाम में फंसे

संवाददाता

मुंबई। पुणे–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से भारी यातायात जाम की स्थिति बन गई है। इस हादसे का सीधा असर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) की बस सेवाओं पर पड़ा है।

यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग द्वारा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात सामान्य होते ही बस सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, इस दुर्घटना के चलते राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 139 बस सेवाएं रद्द करनी पड़ी हैं, जिनमें 73 ई-शिवनेरी और 66 अन्य बस सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, पुणे–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन की कुल 163 बसें और वाहन यातायात जाम में फंसे हुए थे। इनमें सातारा विभाग की 46, सोलापुर की 36, पुणे की 20, सांगली की 18, कोल्हापुर की 13, पालघर की 12, ठाणे की 11 तथा मुंबई विभाग की 7 बसें और वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग ने कहा है कि यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और यातायात सुचारु होते ही बस सेवाओं को जल्द सामान्य कर दिया जाएगा।

आरटीई के तहत प्रवेश अब तक शुरू नहीं, बढ़ी अभिभावकों की चिंता

संवाददाता

पुणे। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। निजी स्कूलों की पंजीकरण प्रक्रिया पहले ही चरण में अटक जाने से हजारों अभिभावक असमंजस में हैं। स्कूलों की ओर से हो रही देरी के कारण आरटीई के तहत प्रवेश का मुद्दा गंभीर बनता जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से तकनीकी समस्याएं और निजी स्कूलों का कम प्रतिसाद देरी के कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि, लगातार तीसरे वर्ष आरटीई स्कूल पंजीकरण प्रक्रिया लंबित रहने से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अंतिम स्कूल सूची कब जारी होगी और उसके बाद वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिला है। आरटीई अधिनियम के अनुसार, निजी बिना अनुदान प्राप्त स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें वंचित और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। बावजूद इसके, कई निजी स्कूल इस नियम की अनदेखी करते हुए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए हैं। इस वर्ष भी तीन बार समय-सीमा बढ़ाने के बाद कई स्कूलों ने पंजीकरण पूरा नहीं किया है। इसे प्रशासन की विफलता माना जाए या स्कूलों की जानबूझकर की गई देरी, इस पर अभिभावकों में नाराजगी है।

इस बीच पुणे दौरे पर आए राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने निजी स्कूलों की आरटीई के प्रति उदासीनता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल आरटीई प्रवेशों को लेकर अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि निजी स्कूलों के लिए एक अलग नियमावली तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि भविष्य में अभिभावकों को निजी स्कूलों पर निर्भर न रहना पड़े। आरटीई का 2200 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित मंत्री भुसे ने यह भी स्वीकार किया कि आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित है। इस राशि को चरणबद्ध तरीके से शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, निजी स्कूलों का आरोप है कि समय पर अनुदान न मिलने के कारण वे आरटीई प्रवेश से बचते हैं। पंजीकरण न करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई? आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा निजी स्कूलों की उदासीनता मानी जा रही है। कई नामी स्कूल आरटीई पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। कानून के तहत यह अनिवार्य होने के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई न होने से स्कूलों का मनोबल बढ़ा है। अभिभावक संगठनों का आरोप है कि स्कूल मुदत लो और समय टालो की नीति अपना रहे हैं। इस संबंध में जिला परिषद की उपशिक्षण अधिकारी आस्मा मोमिन ने बताया कि आरटीई स्कूल पंजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गट शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मंगाई गई है और जिन स्कूलों ने अब तक पंजीकरण नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जारी किए जा रहे हैं। साथ ही, अपंजीकृत स्कूलों की जांच की जा रही है, जिनमें नई और अल्पसंख्यक स्कूलों की जानकारी भी शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरटीई के तहत पात्र स्कूलों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अभिभावक और सामाजिक संगठनों ने शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

Emergency landing at Kolkata airport as Turkish Airlines plane catches fire

KOLKATA: A Turkish Airlines widebody aircraft carrying 236 people made a "full emergency landing" at Netaji Subhas Chandra Bose International Airport in Kolkata Wednesday afternoon after its right engine reportedly caught fire shortly after departure from Kathmandu.

Airport authorities confirmed that all 225 passengers and 11 crew members were unharmed. The aircraft is currently stationed at the Kolkata airport, undergoing a technical inspection.

Flight THY-727, an Airbus A330-300 bound for Istanbul, took off from Nepal's Tribhuvan International Airport (TIA) at 1.29 pm. Within four minutes, the crew detected a malfunction in the right engine. According to Gyanendra Bhul, deputy spokesperson for the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN), the pilot immediately informed the Kathmandu tower and shut down the affected engine.

The aircraft travelled over the Dharke area in Dhading district for approximately 10 minutes to assess the situation. While the crew had the option to return to Kathmandu or divert to Bhairahawa, they determined the aircraft was unfit for long-haul travel and opted for an emergency landing in Kolkata. Subsequently, the plane touched down safely in Kolkata at 3.03 pm.

The emergency landing comes during a period of heightened concern regarding aviation safety. Last week, a Learjet 45 charter aircraft operated by VSR Ventures crashed in Maharashtra's Baramati while landing, killing five people, including Deputy Chief Minister Ajit Pawar. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has since ordered a special audit of the operator.

On June 12, 2025, an Air India Boeing 787-8 Dreamliner crashed into a building in an Ahmedabad suburb seconds after takeoff. The crash, which killed 260 people – 241 on board and 19 on the ground – was attributed to a sudden loss of thrust after fuel control switches reportedly moved to the "cutoff" position.

SURAT GETS RS 10,593 CR DRAFT BUDGET, RS 593 CR HIKE IS ITS HIGHEST YET

SURAT: Surat Municipal Commissioner M Nagarajan on Wednesday presented a draft budget of Rs 10,593 crore for 2025-26, marking a rise of Rs 593 crore – the highest in Surat's history.

No increase in property taxes or user charges was proposed in the draft budget. In the current year, 8 new overbridges will be built in Surat, which is also known as 'Bridge city'. At the same time, Rs 332 crore has been proposed for existing and new roads in the city.

As per the provision, the SMC will spend Rs 5,073 crore as capital budget for development works in 2026-27 while for the same year the revenue income is estimated to be Rs 5,777 crore. Among the revenue income, the biggest part of 29 per cent will be from non-tax revenue and user charges which will be 23 per cent. Around 48 per cent of total expenses will be incurred in the establishment section; in addition, around 19 per cent of revenue will be spent on renovation, repairing, and power charges. SMC has proposed 8 new flyover bridges worth Rs. 540 crores for the next year in the city, to ease the traffic congestion.

The SMC has started preparing to implement the "Urban Green Policy" to make the city greener. Green standards will be set up at the ward level across the city. Special "Green officers" will be appointed for the maintenance of

the environment who will constantly monitor greenery at ward level. Under "Tree Health Card" the health of every three in the city will be surveyed periodically and its proper maintenance. With this initiative, Surat will make a significant contribution to achieving the 'Net Zero' target of the Government of India by 2047 and will become the second city in the country to adopt such a policy.

Special attention is given to developing the famous 'Letchworth – Garden City Concept' as part of modern urban planning in Surat. A feasibility study will be conducted by the municipal administration to examine the possibilities of implementing this concept in the city. An attempt will be made to achieve harmony between the residential area and nature through the Garden City model, thereby improving the living standards of Surat's citizens.

Under the Swachh Vayu Survekshan 2024, conducted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Surat secured 1st rank in the country (among cities with a population over 10 lakh).

The city's major economic activities are done in the diamond and textile industries-dominated areas and the SMC has allocated Rs 22 crore for purchase of latest equipment to deal with fire and rescue operations.

SMC commissioner M Nagarajan said, "Ground-mounted solar park having capacity to generate 10 MW, had been operational in December, wherein over 1.73 crore units of power will be generated, which will help in the reduction of power bills of SMC worth Rs 13 crore per annum."

Apart from this, SMC will introduce a new concept to educate children found begging at traffic signal junctions and other places. For this, SMC authorities will coordinate with Surat district legal Service authorities and start "Signal School" in the near future.

Prioritising women's safety and hygiene in urban infrastructure, Surat Municipal Corporation has emphasized establishing 'Pink Toilets' in busy areas and public spaces. These facilities will ensure safe access for women and include modern features like sanitary pad vending machines and incinerators.

200 UNITS OF FREE POWER FOR 2.23 LAKH J&K FAMILIES: J&K LG SINHA GREENLIGHTS NC'S BIG POLL PROMISE

New Delhi: In a major boost to the ruling National Conference's key poll promise made during the 2024 Assembly elections, the Centre has approved the Jammu and Kashmir government's project to provide 200 units of free electricity to 2.23 lakh Antyodaya Anna Yojana (AAY) families in the Union Territory.

"On the recommendation of J&K government, the Ministry of New and Renewable Energy, GoI, has accorded approval to a project for providing 200 free units of electricity to 2.23 lakh AAY families of Jammu and Kashmir under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna–Utility Led Aggregation (ULA) model," Lt Governor Manoj Sinha said in his address on the opening day of the Budget Session here Monday, adding that it would be implemented soon. Providing 200 units of free electricity to every household was among the National Conference's key electoral promises. In the last Budget, the government had proposed initiating the scheme by first extending the benefit to AAY families.

Highlighting structural changes in the power sector, the Lt Governor said major hydropower projects — Pakal Dul, Kiru, Kwar and Ratle– with a combined capacity of 3,014 MW are under active execution. Over the past five years, 5,708 MVA has been added to the distribution sector and 4,239 MVA to the transmission sector, he added.

The installation of smart prepaid meters is being carried out in mission mode, with 10.44 lakh meters already installed and 100 per cent coverage targeted by 2026–27. This has led to a 9 percent reduction in losses and a 16 per cent increase in revenue realisation, he said.

Parallelly, solarisation of government buildings and households under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is strengthening the Union Territory's renewable energy footprint. More than 6,700 government buildings and over 16,800 households have been solarised, reducing power costs and enhancing energy security, he added.

Terming tourism a vital pillar of J&K's economy, the Lt Governor said 1.78 crore tourists visited the Union Territory in 2025 despite challenges posed by security-related incidents and natural calamities. Recognising tourism as a lifeline, the government undertook confidence-building measures, improved facilitation and strengthened coordination with stakeholders.

परदेशातून येणाऱ्यांसाठी सीमाशुल्क नियम अधिक सुलभ

नवी दिल्ली: परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सीमाशुल्क नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, भारतीय नागरिकांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. तसेच दागिने आणण्याचे नियम आता किमतीऐवजी वजनाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे विमानतळावरील सीमाशुल्क मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. हे नवीन नियम 2 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत.

हवाई किंवा सागरी मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांसाठी शुल्क-मुक्त मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र रस्तेमार्गाने भारतात येणाऱ्या कोणत्याही प्रवाशाला सामान्य शुल्क-मुक्त सूट मिळणार नाही. भारतीय रहिवासी, भारतीय वंशाचे पर्यटक तसेच नॉन-टूरिस्ट व्हिसावर येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी ही मर्यादा 75,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर परदेशी वंशाच्या पर्यटकांसाठी ही मर्यादा

15,000 रुपयांवरून वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. एअरलाईन क्रू मेंबर्ससाठी ही मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच 2,500 रुपये राहणार आहे. दागिन्यांवरील किमतीची मर्यादा रद्द करून आता वजनाच्या आधारावर सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिलेल्या महिला प्रवाशांना 40 ग्रॅमपर्यंतचे दागिने शुल्कमुक्त आणता येतील, तर इतर प्रवाशांसाठी ही मर्यादा 20 ग्रॅम निश्चित करण्यात आली आहे.

गरजेच्या वस्तूंमध्येही बदल करण्यात आले असून, 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा प्रत्येक प्रवासी एक लॅपटॉप शुल्क न भरता आणू शकतो. दुसरा लॅपटॉप आणल्यास त्यावर कस्टम शुल्क आकारले जाईल. पाळीव प्राण्यांनाही आता शुल्क-मुक्त श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी संबंधित प्राणी आयात नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, मौल्यवान वस्तू तात्पुरत्या स्वरूपात परदेशात घेऊन जाताना किंवा परत आणताना कस्टमकडून 'तात्पुरते बॅगेज निर्यात/आयात प्रमाणपत्र' दिले जाणार असून, त्यामुळे परत येताना सामान अडकण्याची अडचण टळणार आहे.

परदेशातून कायमस्वरूपी परत येणाऱ्यांसाठी निवास हस्तांतरणाच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आता सामानांच्या यादीऐवजी परदेशात राहिलेल्या कालावधीनुसार मूल्य मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 12 महिने थांबल्यास 1.50 लाख रुपये , 1 ते 2 वर्षे थांबल्यास 3 लाख रुपये आणि 2 वर्षांपेक्षा अधिक काळ थांबल्यास 7.50 लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळणार आहे. सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी डिजिटल प्रणालीवर भर देण्यात आला असून, प्रवासी आता 'ICEGATE' पोर्टल किंवा सरकारी ॲपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक घोषणा करू शकतील. यामुळे विमानतळावरील रेड चॅनल आणि ग्रीन चॅनल प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी होणार असून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांची लवकरच कर्जमाफी – बावनकुळे

लातूर: कर्जमाफी ही मध्यमवर्गीय व गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लामजना येथे झालेल्या प्रचार सभेत केले. कर्जमाफीबाबत पसरवले जात असलेले गैरसमज दूर करत त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरच जाहीर होणार असून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. कर्जमाफीचा लाभ खरोखरच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या प्रचार सभेत ते औसा तालुक्यातील लामजना येथे बोलत होते. यावेळी मंचावर माजी मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष व बसवराज पाटील आमदार अभिमन्यू पवार, सभापती चंद्रशेखर सोनवणे, ॲड परीक्षीत पवार आदी सह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी गायरान, बंजारा वस्ती व वडार समाजासाठी मोठी घोषणा केली.

अभिमन्यू, तुम्ही सर्व गावांची यादी तयार करा. मी एक शासन आदेश काढून गायरानवर, बंजारा वस्तीत किंवा इतर वस्तींमध्ये राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांचे कबाले वाटप करून देण्याची जबाबदारी घेतो, असे त्यांनी जाहीर केले. घरकुलासाठी कमाल मर्यादा न मिळालेल्या कुटुंबांनाही न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

भारत ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्रात सामील

नवी दिल्ली: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाद्वारे वाणिज्य भवन, नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात भारत, 'ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्र' (बीसीआयसी) यामध्ये सामील झाला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या औद्योगिक विकास संघटनेच्या सहयोगाने सुरू केलेले 'ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्र, ब्रिक्स देशांमधील उत्पादन कंपन्या आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना एकात्मिक समर्थन सेवा प्रदान करणारे एक-सेवा केंद्र म्हणून काम करते, ज्याचा उद्देश उद्योग 4.0 क्षमता मजबूत करणे हा आहे.

या प्रसंगी, डीपीआयआयटी आणि युनिडो यांच्यात एक ट्रस्ट फंड करार करण्यात आला. डीपीआयआयटीचे आर्थिक सल्लागार अग्रिम कौशल आणि युनिडोचे संचालक डॉ. क्रिस्टियानो पासिनी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे बीसीआयसीच्या आराखड्यात भारताच्या सहभागाला औपचारिक मान्यता मिळाली.

ब्रिक्स औद्योगिक क्षमतांसाठी भारतातील केंद्र म्हणून राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डीपीआयआयटीच्या धोरणात्मक मार्गदर्शनाखाली आणि युनिडोच्या तांत्रिक सहाय्याने,राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्र सोबत भारताच्या सहभागाचे नेतृत्व करेल आणि क्षमता निर्माण, उत्पादकता वाढ आणि प्रगत उत्पादन पद्धतींचा अवलंब करण्यात योगदान देईल.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद डीपीआयआयटीचे सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी भूषवले आणि एनपीसीच्या महासंचालक नीरजा शेखर यांच्यासह डीपीआयआयटी, एमएसएमई मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, युनिडोचे प्रतिनिधी आणि उद्योग भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) यांचे वरिष्ठ अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.

लॉन्च हुआ तापसी पन्नू की अस्सी का ट्रेलर

अभिनेत्री तापसी पन्नू निर्देशक अनुभव सिन्हा की आगामी इन्वेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म अस्सी के जरिए एक बार फिर कोर्टरूम जॉनर में नजर आएंगी। फिल्म के मोशन पोस्टर को मिले शानदार प्रतिसाद के बाद प्रमोशन अभियान की शुरुआत मंगलवार को जयपुर से की गई। इस दौरान तापसी पन्नू ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में फिल्म की टीम ने बड़े पर्दे पर ट्रेलर प्रदर्शित किया। जिसे तापसी ने मीडिया प्रतिनिधियों,पत्रकारों,फैंस और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ देखा।

उन्होंने फिल्म की कहानी, विषयवस्तु और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा भी की। फिल्म के मोशन पोस्टर ने पहले ही अपने सशक्त संदेश और गंभीर टोन के कारण दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी थी। जयपुर में ट्रेलर शोकेस के दौरान दर्शकों ने फिल्म के कोर्टरूम माहौल और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानी को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
फिल्म अस्सी एक तेज रफ्तार इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। जो देश में रोजाना दर्ज होने वाले करीब 80 यौन उत्पीड़न मामलों की सच्चाई से प्रेरित है। फिल्म में तापसी पन्नू के साथ कनी कुसरुति,रेवती,मनोज पाहवा,कुमुद मिश्रा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब अहम भूमिकाओं में हैं।
वहीं नसीरुद्दीन शाह,सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा विशेष प्रस्तुतियों में नजर आएंगे।
गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रस्तुत इस फिल्म का निर्माण बेनारस मीडिया वर्क्स के बैनर तले भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म 20 फरवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नेटफ्लिक्स ने पेश किया नया कंटेंट स्लेट

ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को अपनी आगामी भारतीय सीरीज और फिल्मों की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस साल दर्शकों को इतिहास, कोर्टरूम ड्रामा, कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर कंटेंट देखने को मिलेगा। सैफ अली खान की फिल्म 'हम हिंदुस्तानी' का टीजर जारी किया गया है, जो भारत के पहले चुनाव की सच्ची कहानी से प्रेरित है। इसके अलावा विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना की 'मुसाफिर कैफे', विनीत कुमार सिंह की 'हैलो बच्चों' और कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'ढिंढोरा 2' का भी ऐलान किया गया है।
नेटफ्लिक्स ने अनिल कपूर और विजय वर्मा की सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का टीजर जारी किया है, वहीं सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' का भी ऐलान किया गया है, जिससे सनी देओल ओटीटी डेब्यू करेंगे। कॉमेडी के मोर्चे पर कपिल शर्मा की हिट सीरीज 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे और पांचवें सीजन की घोषणा की गई है।
साउथ कंटेंट पसंद करने वाले दर्शकों के लिए 'सुपर सुब्बू', आर. माधवन और गुलशन देवैया की तमिल क्राइम सीरीज 'लेगेसी', और फिल्म 'मेड इन कोरिया' को कई भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा सीरीज 'लव' का भी टीजर रिलीज हुआ है। 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल और आनंद देवरकोंडा की जोड़ी फिल्म 'तक्षककुडु' में नजर आएगी, जो पांच भाषाओं में रिलीज होगी। वहीं सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' और तापसी पन्नू की 'गांधारी' का भी पोस्टर जारी कर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस तरह नेटफ्लिक्स ने 2026 में भारतीय दर्शकों के लिए बड़े और विविध कंटेंट पैकेज का ऐलान कर दिया है।

चिरंजीवी की 'विश्वंभरा' में देरी पर मेकर्स ने दिया जवाब

टॉलीवुड के मेगास्टार चिरंजीवी एक बार फिर अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारु' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और हर वर्ग के दर्शकों का दिल जीत लिया। अनिल रविपुडी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सफलता के बाद अब फैंस की नजरें चिरंजीवी की अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'विश्वंभरा' पर टिकी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि 'विश्वंभरा' की शूटिंग 'माना शंकरा वरप्रसाद गारु' से काफी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस सवाल का जवाब हाल ही में 'कपल फ्रेंडली' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सामने आया। यूवी क्रिएशंस से जुड़े अजय कुमार ने मंच से खुलासा किया कि फिल्म के पहले टीजर में दिखाया गया CGI और विजुअल इफेक्ट्स दर्शकों को खास पसंद नहीं आए थे। दर्शकों की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेते हुए मेकर्स ने फिल्म के VFX पर दोबारा काम करने का फैसला लिया। अजय कुमार ने साफ कहा कि 'विश्वंभरा' एक बड़े स्केल की फैंटेसी फिल्म है, जिसमें कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी बेहद अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में मेकर्स क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि दूसरे टीजर में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली विजुअल्स दिखाए गए हैं और अब फिल्म लगभग पूरी होने की कगार पर है। रिलीज डेट को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि प्रोड्यूसर वामसी जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। वहीं, फिल्म की दमदार स्टारकास्ट ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। त्रिशा फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी, जबकि कुणाल कपूर विलेन के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा, म्यूजिक की कमान एम.एम. कीरवाणी के हाथ में है, जो फिल्म के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है।

सेहत के नाम पर गलती न करें, पेपर कप से रहें सावधान

आजकल चाय या कॉफी पीने के लिए पेपर कप का इस्तेमाल आम हो गया है। लोग इन्हें सेहत और पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की राय इससे बिल्कुल अलग है। विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक पेपर कप में गर्म पेय पदार्थ पीना सेहत के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है और इससे कैंसर व थायरॉइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

दरअसल, पेपर कप केवल कागज से नहीं बनते। इन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए अंदर की परत में मोम या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब इनमें गर्म चाय या कॉफी डाली जाती है, तो कप की अंदरूनी परत से हानिकारक केमिकल्स निकलकर पेय पदार्थ में मिल सकते हैं। यही केमिकल्स शरीर में जाकर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं।

पेपर कप से होने वाले नुकसान

डॉक्टर्स के मुताबिक, पेपर कप बनाने में केमिकल्स और माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। गर्म चीजों के संपर्क में आने पर ये तत्व घुलकर शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे थायरॉइड संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
पेपर कप में बिसफेनोल (BPA) जैसे हानिकारक केमिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। गर्म चाय या कॉफी डालने पर ये केमिकल्स

पेय में मिल जाते हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा, पेपर कप पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डालते हैं। इनमें मौजूद सूक्ष्म कण गर्म पेय के साथ शरीर में चले जाते हैं, जिससे एसिडिटी, पेट दर्द और अन्य गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं।

पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक

पेपर कप सिर्फ सेहत ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इन्हें पूरी तरह से रिसायकल करना मुश्किल होता है। जलाने पर ये जहरीले केमिकल्स छोड़ते हैं, जो हवा को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।

क्या करें इस्तेमाल?

अगर आप खुद को इन खतरों से बचाना चाहते हैं, तो पेपर कप का इस्तेमाल कम से कम करें। इसकी जगह चीनी मिट्टी (सिरेमिक), कांच या स्टेनलेस स्टील के कप में चाय-कॉफी पीना बेहतर विकल्प है। इससे न केवल आपकी सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। पेपर कप दिखने में भले ही सुरक्षित लगें, लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। इसलिए अगली बार चाय या कॉफी पीते समय कप का चुनाव सोच-समझकर करें।

वजन बढ़ाना है तो डाइट में शामिल करें ये हाई कैलोरी फूड्स

जहां एक तरफ मोटापा आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो दुबलेपन से परेशान हैं। दुबले-पतले शरीर वाले लोगों को अक्सर समाज में अनचाहे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। ऐसे में वजन बढ़ाने के लिए लोग अक्सर महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स ऐसे भी हैं जो हेल्दी तरीके से वेट गेन में मदद कर सकते हैं।

अंडेः मसल्स ग्रोथ का मजबूत आधार

अंडे वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन फूड माने जाते हैं। इनमें प्रोटीन और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। अगर किसी को अंडे से एलर्जी नहीं है, तो वह दिन में तीन अंडे तक आसानी से खा सकता है। अंडे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और एनर्जी भी प्रदान करते हैं।

दूधः वजन और ताकत दोनों के लिए फायदेमंद

दूध को डेली डाइट में शामिल करना वजन बढ़ाने का आसान तरीका है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की अच्छी मात्रा होती है। दूध न सिर्फ वजन बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने और हड्डियों को ताकत देने में भी सहायक होता है। यह कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है।

चावलः हाई कैलोरी का आसान विकल्प

कई लोग यह नहीं जानते कि चावल वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जिनकी भूख कम लगती है या जिनका पेट जल्दी भर जाता है। चावल खाने से शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती है।

ड्राई फ्रूट्सः छोटे लेकिन असरदार

काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इनमें कैलोरी, एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इन्हें ग्रीक दही, चीज, मीट या प्रोटीन शेक के साथ मिलाकर खाया जा सकता है।

नट बटरः हाई कैलोरी सुपरफूड

नट बटर दुबले लोगों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसे नाश्ते में शामिल करने से शरीर को अच्छी मात्रा में कैलोरी मिलती है। स्मूदी, दही या क्रैकर्स में नट बटर मिलाकर झटपट हाई कैलोरी स्नैक तैयार किया जा सकता है। अगर किसी को मूंगफली या किसी खास नट से एलर्जी है, तो सेफ सीड बटर का विकल्प अपनाया जा सकता है।

ज्यादा मीठे फलः डायबिटीज और वजन घटाने वालों के लिए चेतावनी

आज के समय में लोग फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं। आमतौर पर फल को पूरी तरह से हेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ फलों में नेचुरल शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है। ज्यादा शुगर वाले फल डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन से फलों में शुगर ज्यादा होती है और इन्हें किस मात्रा में खाना सही रहता है।

- **आम** - आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसका स्वाद हर किसी का दिल जीत लेता है। लेकिन आम में नेचुरल शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। 100 ग्राम आम में लगभग 14-16 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि इसमें विटामिन C और फाइबर भी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसकी अधिकता ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है।
- **अंगूर** - छोटे-छोटे अंगूर दिखने में भले ही हल्के लगते हों, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा काफी होती है। 100 ग्राम अंगूर में लगभग 15-16 ग्राम शुगर होती है। यह ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। हालांकि अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन K मौजूद होता है, जो दिल की सेहत और हड्डियों के लिए अच्छा है।
- **लीची** - गर्मियों का लोकप्रिय फल लीची स्वाद में जितनी मीठी होती है, उसमें उतनी ही अधिक शुगर भी होती है। 100 ग्राम लीची में लगभग 15 ग्राम शुगर पाई जाती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकती है। हालांकि लीची में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन सोच-समझकर करना चाहिए।
- **केला** - केला एक ऐसा फल है जिसे एनर्जी बूस्टर माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें शुगर भी अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 12-14 ग्राम शुगर होती है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह वजन बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है। हालांकि केले में पोटैशियम और फाइबर होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए।
- **अनानास** - अनानास का स्वाद खट्टा-मीठा होता है और यह जूस में भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन अनानास में भी शुगर की मात्रा कम नहीं होती। 100 ग्राम अनानास में लगभग 10-13 ग्राम शुगर होती है। इसका जूस पीने से ब्लड शुगर जल्दी बढ़ सकता है, क्योंकि जूस में फाइबर कम हो जाता है और शुगर जल्दी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अनानास को सीमित मात्रा में और फ्रेश कट फॉर्म में खाना बेहतर है।
- **चेरी** - चेरी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही मीठी होती है। 100 ग्राम चेरी में लगभग 13 ग्राम शुगर होती है। छोटे आकार में होने के कारण लोग इसे अक्सर ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, लेकिन यह ब्लड शुगर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि चेरी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं।
- **अंजीर** - अंजीर ताजे और सूखे दोनों रूप में खाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। 100 ग्राम अंजीर में लगभग 16-17 ग्राम शुगर पाई जाती है। सूखे अंजीर में शुगर की मात्रा और भी बढ़ जाती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए अंजीर का सेवन सावधानी से करना चाहिए। हालांकि इसमें कैल्शियम और आयरन भी होता है, जो हड्डियों और खून के लिए फायदेमंद है।

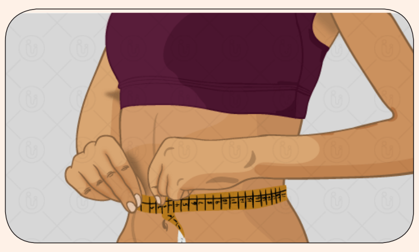

जनपद में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र व गौशालाओं का होगा औचक निरीक्षण, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई: सीडीओ

हरे चारे, सीसीटीवी, कैटल फीड और ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश

देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। जनपद में संचालित बृहद गौ संरक्षण केन्द्रों एवं गौशालाओं का शीघ्र ही औचक निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) श्री जुनैद अहमद ने विकास भवन सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण मा. मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए गौशालाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्त बृहद गौ संरक्षण केन्द्रों में गोवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान यदि हरा चारा मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसील मऊरानीपुर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कैटल फीड का उत्पादन किया जा रहा है तथा सभी गौशालाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे समूह से कैटल फीड क्रय कर गोवंश को उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया गया कि जनपद के 269 गौ आश्रय स्थलों में 269 सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 197 कैमरे कंट्रोल रूम से लिंक हैं तथा केवल 157 कैमरे ही वर्तमान में लाइव हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने सभी सीसीटीवी कैमरों को दस दिन के भीतर शत-प्रतिशत लाइव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी नामित कर तकनीकी टीम के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने के आदेश दिए, ताकि विकास भवन स्थित कमांड सेंटर से सभी गौशालाओं एवं गौ आश्रय स्थलों की प्रभावी निगरानी की जा सके। सीडीओ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक गौशाला में गोवंश को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। त्रिपाल लगाकर ठंडी हवाओं से बचाव, भूसा, स्वच्छ पानी एवं नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्वस्थ एवं बीमार गोवंश का प्राथमिकता के आधार पर उपचार कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मार्गों एवं हाईवे पर गोवंश सड़क पर न आए, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं तथा आवश्यकता अनुसार नई गोशालाओं का निर्माण भी कराया जाएगा। गो आश्रय स्थलों से संबंधित सभी अभिलेख पूर्ण किए जाएं और निरीक्षण के दौरान यदि अभिलेखों में कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र की गौशालाओं का नियमित भ्रमण करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल रिपोर्ट कर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार सिंह, पीडी डीआरडीए राजेश कुमार, डीसी मनरेगा शिखर श्रीवास्तव सहित समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन

सुदूरवर्ती क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को मिलेगा त्वरित न्याय व योजनाओं का लाभ

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव में मंगलवार को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। यह मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त दिव्यांग, उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार, उन्नाव में आयोजित की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनकर उनका स्थानीय स्तर पर समाधान करना है, ताकि उन्हें न्याय के लिए भटकना न पड़े।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव, ज्योति त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मोबाइल कोर्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की मूल भावना के अनुरूप आयोजित की गई है। इसके माध्यम से उन दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जो अब तक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं या जिन्हें इन योजनाओं की समुचित जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि जनपद के कई ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से न केवल उनकी शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा, बल्कि उन्हें सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं और दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। मोबाइल कोर्ट के दौरान समाज में दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें पूर्ण और प्रभावी भागीदारी दिलाना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस आयोजन में दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पेंशन, सहायक उपकरण, प्रमाण पत्र, आवास सहित अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को भी सुना जाएगा। जिला प्रशासन ने जनपद के सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। जिन दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या है, वे निर्धारित तिथि को विकास भवन सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट में प्रार्थना पत्र के साथ समय से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।

गुफा में छुपे आतंकियों पर सुरक्षा बल की नजर

संवाददाता

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक प्राकृतिक गुफा में छुपे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो आतंकवादियों पर सुरक्षा बल अंतिम हमले की तैयारी कर रहे हैं। रात भर किसी भी प्रकार की गोलीबारी की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे रामनगर के जाफर वन क्षेत्र में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त तलाशी टीमों ने गुफा के अंदर आतंकवादियों का पता लगाया। इसके बाद एक घंटे से अधिक समय तक भीषण गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी घायल हो गया लेकिन वह अपने साथी के साथ गुफा में घुसने में सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे दोनों ने अंधेरे का फायदा उठाकर गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश की सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने उन्हें दोबारा गुफा में घुसने पर मजबूर कर दिया। पैराट्रूपर्स और डॉग स्क्वाड सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए तुरंत भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि रात भर कोई गोलीबारी नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से इलाके, खासकर गुफा के आसपास कड़ी निगरानी रखी। उन्होंने कहा कि गुफा में छुपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए अंतिम हमला करने की तैयारी चल रही है।

शबे-बारात: इबादत की रात, मगफिरत की दुआ और अकीदत का सैलाब

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 15वीं रात, यानी 'शबे-बारात' नगर व क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और अकीदत के साथ मनाई गई। इस मुकद्दस रात के मौके पर सभी मस्जिदों और खानकाहों/दरगाहों में इबादत का विशेष दौर चला। अकीदतमंदों ने पूरी रात जागकर खुदा की बारगाह में नमाज, कुरान की तिलावत और तौबा (क्षमा याचना) की।शबे-बारात के खास मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोज़ा रखा। मान्यता है कि इस रात खुदा अपने बंदों के लिए मगफिरत (माफी) के दरवाजे खोल देता है और आने वाले साल के लिए उनके नसीब का फैसला होता है। रोज़ेदारों ने शाम को इफ्तार के बाद मस्जिदों का रुख किया, जहां ईशा की नमाज के बाद विशेष दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ। नगर व आसपास के क्षेत्रों में स्थित सभी मस्जिदों, दरगाहों और धार्मिक स्थलों को बिजली की झालरों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। रात भर मस्जिदों में तस्बीह और जिक्र का दौर चलता रहा। उलेमाओं ने इस रात की फजीलत पर रोशनी डालते हुए लोगों को नेक राह पर चलने और इंसानियत की सेवा करने का संदेश दिया। परंपरा के अनुसार, लोग बड़ी तादाद में कब्रिस्तान भी पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पूर्वजों और दुनिया से रुखसत हो चुके अपनों की कब्रों पर फातिहा पढ़ा, फूल चढ़ाए और उनके गुनाहों की माफी व रूह के सुकून के लिए दुआएं मांगी। कब्रिस्तानों में रोशनी के विशेष इंतजाम किए गए थे और लोगों की आवाजाही पूरी रात बनी रही। दुआओं के दौरान मुल्क में अमन-चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए भी विशेष प्रार्थनाएं की गईं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस रहमतों भरी रात में अल्लाह की इबादत में मशगूल नज़र आया।

खेमचंद भाजपा विधायक दल के नेता: मणिपुर भाजपा

संवाददाता

इंफाल। भाजपा की मणिपुर यूनिट ने आज कहा कि मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह का भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर चुनाव, हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के केंद्र के इरादे को दिखाता है। सिंह के नेता चुने जाने के बाद राज्य में सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि राज्य में बहुत जल्द नई सरकार का गठन होगा। मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता लाइमयूम बसंत शर्मा ने कहा कि इस फैसले से करीब एक साल के राष्ट्रपति शासन के बाद लोकप्रिय सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम युमनाम खेमचंद को विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाने की सराहना करते हैं। राज्य में करीब एक साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। शर्मा ने सिंह को पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक बताया, जिनकी विधायकों में सबसे साफ-सुथरी छवि है। उन्होंने कहा कि वह बातों के बजाय काम में विश्वास करते हैं, जैसा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से साफ है। शर्मा के अनुसार, सिंह का चुनाव राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के केंद्र के साफ इरादे को दिखाता है और वह नागा और कुकी सहित सभी समुदायों को स्वीकार्य हैं।

दिल्ली के परिवारों को होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगाई से राहत देने की दिशा में एक अहम और जनकल्याणकारी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज उस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026 से दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष दो एलपीजी सिलेंडर के बराबर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना दिल्ली सरकार की लक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह कल्याण नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की निर्धारित राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से परिवार के मुखिया के आधार-सीडेड बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना की प्रमुख विशेषताएं : इस योजना से दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवार लाभान्वित होंगे। यह योजना सार्वभौमिक है और एलपीजी अथवा पीएनजी उपयोग करने वाले सभी राशन कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगी। सहायता दो अवसरों (होली और दिवाली) पर प्रदान की जाएगी, चाहे उस महीने सिलेंडर की रिफिलिंग कराई गई हो या नहीं। दिल्ली में वर्तमान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये प्रति सिलेंडर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को केंद्र सरकार की 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को समायोजित करने के बाद 553 रुपये प्रति सिलेंडर की सहायता दी जाएगी। गैर-उज्ज्वला राशन कार्ड धारक परिवारों को 853 रुपये प्रति सिलेंडर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 242.77 करोड़ रुपये होगा, जो एलपीजी कीमतों, भारत सरकार की सब्सिडी तथा लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए स्पष्ट बजटीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि त्योहारों के समय गरिमा और राहत सुनिश्चित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन दिया है। दिल्ली सरकार की यह योजना उसी दूरदर्शी सोच का विस्तार है, जिसमें कल्याण को सब्सिडी की राजनीति नहीं, बल्कि नियम आधारित और पारदर्शी शासन के रूप में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह योजना भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा थी और दिल्ली सरकार चरणबद्ध रूप से अपने सभी वादों को ज़मीन पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि शासन की नीयत और क्रियान्वयन की क्षमता का प्रमाण है। यही सुशासन का फर्क है।

गुलमर्ग और पहलगाम में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया

संवाददाता

श्रीनगर। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिसॉर्ट्स में रात का तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे गिर गया जबकि घाटी के बाकी हिस्सों में गर्म रात का आनंद लिया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो मंगलवार रात की तुलना में 2.7 डिग्री कम है। पहलगाम, दक्षिण कश्मीर में एक पर्यटन स्थल जो अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है का तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री कम होकर शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। श्रीनगर में मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसमी औसत से 3.6 डिग्री अधिक था।

भारत-अमेरिका डील से युवाओं को रोजगार: पीयूष गोयल

संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह डील देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और युवाओं के लिए रोजगार तथा व्यापार के नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ से संबंधित हालिया घोषणा के बाद गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह समझौता भारत के लिए अब तक का सबसे बेहतर सौदा है। उन्होंने बताया कि भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा मिलेगा।

गोयल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत संबंधों का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत के दौरान भारत के राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि यह डील देश के औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ निवेश और उत्पादन के नए रास्ते खोलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी और इससे देश के उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। गोयल ने कहा कि यह समझौता राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इससे भारत के मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव तैयार होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस डील से देशभर के उद्योगों, किसानों और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालय: कंटेश्वर सिंह चाल, अपोजीट एकताड़ मंडल, साईं बाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई- 400051, Mob. 8898271111**